the core sector. So far as the second part of the question is concerned, this particular type of steel is used for stamping. By and large, the small scale industries established in the backward areas are not primarily concerned with this type of strip. There are certain guidelines for that. As regards the suggestion of the hon. Member for fixing a certain quota for the backward regions, it is a matter to be looked into. I cannot say anything off-hand.

SHRI A. G. KULKARNI: I am sure that it will be looked into.

MR. CHAIRMAN: I think he has answered the question.

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : श्रीमन, इस समय हमारे देश में जो उत्पादन की स्थिति है उसमें केपेसिटी का पूरा युटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि कई क्षेत्रों में इलेक्ट्रीसिटी की हन्ड्रेड परसेन्ट कट हुई है । ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन उत्पादन के क्षेत्रों में पूरी केपेसिटी का युटिलाइजेशन हो, इसके लिए सरकार तत्काल क्या कदम उठाएगी ? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हैं उनको ये चीजें उचित दाम पर और समय पर मिल सकें और उनकी समस्याओं का ठीक प्रकार से समाधान करने के लिए क्या आप कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव की कोई मीटिंग बुला कर, उनको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनके संबंध में कोई कदम उठाएंगे ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: So far as the first part of the question of the hon. Member is concerned, I do agree with him that the power constraint is one of the major reasons follower utilisation of capacity not only? in the steel sector but in almo^r, allj the sectors of industry.

SHRI KALYAN ROY: In Rourkela. there is surplus power.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I have already replied why capacity utilisation in Rourkela is low. And still, there is power constraint and the hon. Member should know it. Secondly, Sir, naturally, we cannot expect that immediately the power position would improve. And the hon. Member's party was in charge of ruling this country for more than two years and he is well aware of the decisions they had taken. So far as the distribution of raw materials to the consumer industries and to form a committee like that is concerned, that is a major policy decision and I don't think that it comes within the purview of this question.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: I would like to know whether any assessment has been made about the total domestic requirement of these silicon steel sheets and how much quantity is imported from outside.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The total demand is expected to be 1,22,400 tonnes in 1979-80 and 1,39,800 tonnes in 1980-81. The indigenous availability is 65,000 tonnes and 79,000 tonnes respectively to meet the indigenous demand of hot-rolled silicon sheets.

MR. CHAIRMAN: Now, we will go on to the next question. Shri Sunder Singh

निर्धन लोगों को कानूनी सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में भगवती समिति की सिफारिशें

***2. श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : †**
श्री हरी शंकर भाभड़ा :
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री 9 जुलाई, 1979 को अतारांकित Bhandari.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sunder Singh Bhandari.

प्रश्न 48 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस अंतर-विभागीय समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जो निर्धन लोगों को कानूनी सहायता दिये जाने के संबंध में भगवती समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिये गठित की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने भगवती समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है या करने का विचार रखती है ?

JRecOmmendationG of Bhagwati Committee on teffai »id to Poor

*2. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: % SHRI HARI SHANKAR BHABHRA: SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 48 given in the Rajya Sabha on the 9th July,, 1979 and state:

(a) whether Government have received the report from the inter-departmental Committee, which was set up to examine the recommendations of the Bhagwati Committee on legal aid to the poor;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what action Government have taken or propose to take on the recommendations made by the Bhagwati Committee?]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री शिव शंकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है सरकार ने भगवती समिति द्वारा की गई सिफारिशों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए एक अन्तर-विभागीय समिति गठित की है । उक्त समिति भगवती समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी उस पर सरकार सम्यक ध्यान देगी ।

t[ ] English translation. JThe question was actually asked on Singh Bhandari.

ttTHE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHIV SHANKAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) As the Hon'ble Members are aware, Government have constituted an Inter-Departmental Committee to undertake a detailed study of the recommendations made by the Bhagwati Committee. Government will give due consideration to the report, which will be submitted by the said Committee, for implementing the recommendations of the Bhagwati Committee.]

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : श्रीमन, इस सवाल में भी 9 जुलाई, 1979 को पूछे गये सवाल का हवाला दिया गया है । उस दिन भी यह जवाब दिया गया—

"The Inter-departmental Committee set up for examining the recommendations of the Bhagwati Committee has to prepare a paper for the consideration of the Government. The paper is in the process of finalisation and is yet *to* be submitted to the Government."

9 जुलाई 1979 को यह जवाब दिया गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस जवाब के बाद क्या किसी तरह की प्रगति इस मामले में हुई है या अभी

the uoor of the House by Shri Sunder

भी वह प्रोसेस आफ फाईनलाइजेशन में ही कागज पड़ा हुआ है ?

श्री शिव शंकर : माननीय सदस्य ने जो 9 जुलाई, 1979 के प्रश्न के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया है, यह सही है कि उसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है और बड़ा खेद यह है कि पिछली गवर्नमेंट ने इस ताल्लुक से ज्यादा कोई कदम नहीं उठाया ।

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : श्रीमन, मुझे अफसोस है कि जहां ब्यूरोक्रेसी कंसर्न है वहां सरकार को लाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जब इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी का यहां उल्लेख है और इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी अगर रिपोर्ट तैयार नहीं करती तो मंत्री जी को यह भी याद होना चाहिए कि 1978–79 के बजट में भी 'एड टु दि पुवर' के लिए रकम इयरमार्क की गई थी लेकिन इस रिपोर्ट के न आने की वजह से वह काम में नहीं लाई जा सकी । 1979–80 के बजट में भी इसके लिए रकम इयरमार्क की गई । तो यह ब्यूरोक्रेटिक सेट अप इस रिपोर्ट को तैयार करे ताकि गरीब लोगों को कानूनी सहायता दी जा सके, इसके लिए सरकार नौकरशाही मे रिपोर्ट जल्दी प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री शिव शंकर : मैं मेम्बर के इस ब्यू के साथ सहमत हूं चूंकि यह गरीब लोगों का मामला है और उनकी मदद का सवाल है इस वास्ते हमें जल्दी से जल्दी इस ताल्लुक से कदम उठाना है और इसके लिये अन्तर्विभागीय जो समिति है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द हमारे सामने आये और हम उसके ऊपर कुछ न कुछ फैसला करें । मैं यह आश्वासन जरुर देना चाहता हूं कि जहां तक अन्तर्विभागीय समिति का सवाल है जल्द से जल्द हम रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और मैं फिर इस हाउस के सामने आकर यह अवगत कराऊंगा कि हमने रिपोर्ट प्राप्त कर ली है और उस ताल्लुक से हम क्या काम करेंगे हम इसके पीछे पड़े हुए हैं।

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : पीछे मत पड़िये, काम करिये ।

श्री शिव शंकर : पीछे पड़ने का मतलब कि काम करना । अगर आप पीछे नहीं पड़ेंगे तो काम नहीं होगा ।

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Dhabc.

श्री हरी शकर भाभड़ा : सभापति महोदय, मेरा नाम है ।

MR. CHAIRMAN: Questions w-U be asked one by one.

SHRI HARI SHANKAR BHABHRA: You have to call me first. My name is there in the question list.

इसीलिये मैंने निवेदन किया था ।

MR. CHAIRMAN: Yes, Shri Hari Shankar Bhabhra. I am not aware of the procedure. You will have to forgive me if I make mistakes

श्री हरी शंकर भाभड़ा : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वे जब तक इन्टर-डिपार्टमेन्टल कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें, सरकार की भी इस बारे में कुछ नीतियां होंगी । गरीबों को कानूनी सहायता देने के लिये उस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कौन कौन से कोर्ट शामिल किये जायेंगे, इस प्रकार के कोई निर्देश क्या सरकार की तरफ से उस कमेटी के मेम्बरों को दिये जायेंगे और क्या सरकार यह उचित समझती है कि इस कानूनी सहायता को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बढ़ाया जाये ?

श्री शिव शंकर : मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सहायता का सवाल है हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की हद तक भी इस सहायता को गरीब भाइयों को देंगे । जहां तक लीगल एड जल्दी से जल्दी गरीब लोगों को देने का सवाल है उस ताल्लुक से ज्यों ही हमारी मिनिस्ट्री बनी हमने इस बारे में अपनी पॉलसी क्लियर कर दी और हमने यह कह दिया कि लीगल एड स्कीम को हम जल्द से जल्द इम्प्लीमेन्ट कर देंगे ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि हर सतह से नीचे से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, गरीबों की सहायता करने की व्यवस्था की जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की गाइड-लाइन्स कमेटी को दी है या नहीं दी है क्योंकि हमारे मन में सन्देह इसलिये पैदा होता है कि इस ही सरकार के द्वारा पहले 1975 में इस प्रकार के संदेह पैदा किये गये थे कि वह वकालत के पेशे का ही राष्ट्रीकरण करना चाहती है। इस पृष्ठभूमि में गरीबों को सहायता दी जाय किन्तु सरकार वकालत के पेशे का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहती, क्या इस बारे में वे मुझे आश्वस्त नहीं करेंगे ?

श्री शिव शंकर : जहां तक गाइड-लाइन्स का सवाल है, सरकार ने किसी किस्म की कोई गाइड-लाइन्स यह जो अन्तर्विभागीय समिति है उसको नहीं दी है। जहां तक नेशनलाइजेशन का सवाल है वकीलों के लिए अभी हमने इस पर कोई सोच विचार नहीं किया है।

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: In the background of this Committee's Report and in the background of the Government's decision in 1975-76, this question does not arise. Therefore, can I take it from the Minister that h_e would not deny the possibility of nationalisation?

MR. CHAIRMAN: That, I think, has been answered. That has been effectively answered.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I want to have a very clear cut answer from the Government; yes or no.

SHRI S. W. DHABE: May I know from the hon. Minister whether it i3 not a fact that this Legal Aid Committee's Report was pending with the Government for the last three years and the Government and the Law Minister were not taking any interest in it? The interest if at all, was only lukewarm. I met the Law Minister a number of times and only Rs. 1 lakh was sanctioned in the Budget for the whole year. And not a single pie they could spend because they waited for the departmental committee report. So this is a very serious question in which justice is not possible for the poor people and the High Courts and the Supreme Court have become the places for those who can spend a lot of money. Therefore,, may I know from the hon. Minister—as the State Governments like Maharashtra and Andhra Pradesh have appointed Advisory Legal Aid Committees to implement this scheme instead of waiting for the Departmental Committee report—whether he will appoint a committee at the national level for legal aid to the poor as appointed by the State Governments? i would also like to know whether at least a sum of Rs. 50 lakhs will He allocated in the next Budget for legal aid to the poor.

MR. CHAIRMAN: The question is narrow aS"to what you are doing. That is what he wants to know.

SHRI KALYAN ROY: Sir, we are also waiting on this side to put a question.

MR. CHAIRMAN: I must tell you that legal aid question is an important question and I will allow more questions.

DR. RAFIQ ZAKARIA; Therefore, you must look to this side also. There must be equitable distribution.

MR. CHAIRMAN: I am doing it strictly in the chronological order.

DR. RAFIQ ZAKARIA: You have to go party-wise. There is no chronological order. If you allow one or two Members from the other .side, you have to allow one or two Members from this side also.

MR. CHAIRMAN: I did not know it.

SHRI KALYAN ROY: Sir, the middle side is also important. While you allow Members from both +hese sides, you have to allow Members from the middle also.

SHRI RAMANAND YADAV: This is your discretion, Sir. You may call anybody whosoever catches your eye.

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, this question has taken 20 minutes already. You may also realise that other questions are equally important.

SHRI SHIV SHANKAR: Mr. Chairman,, Sir, I agree that the report was submitted on 31st August, 1977. My friend was trying to say that the previous Minister was lukewarm. That is a matte$_r$ f°r his knowledge. So far as I am concerned, I do not know anything about it. It is true that only Rs. 1 lakh were earmarked which is highly insufficient. Now, with regard to advisory bodies and others that are working in different States, they have nothing to do with the Central Government. They are doing it on their own and the State Governments themselves are coming forth with the help to have the advisory body reconstituted and in some cases, certain voluntary organisations are also doing very good work and I would congratulate all of them. So far as we are concerned, I cannot at this stage tell my friend, because I have also to go with begging bowl to the Finance Minister,, that I will be able to secure Rs. 50 lakh$_s$ but I can assure the House that I will try to secure as much money as possible because legal aid is the article of our faith.

SHRI S. W. DHABE: Sir, my question is not replied to my question was whether 'he will constitute a icom-mittee at the Central level for legal aid a$_a$ was constituted by the State Governments at the State level.

SHRI SHIV SHANKAR: As I said, still the matter is being processed. We do not know what type of dimensions the problem is going to present and I can assure the Members....

SHRI KALYAN ROY: The dimension is quite big.

SHRI SHIV SHANKAR: According to our concept, legal aid does not merely mean a few rupees to be spent for the poor for their cause in the courts. We further feel that legal aid would further mean that there should be some machinery which must make the poor people in the villages and in the distant places aware of their rights under the various laws also. Therefore, multi-dimentional aspects of the problem have got to be studied and if it becomes necessary, this Government would never shirk the responsibility of appointing a committee at th$_e$ earliest.

DR. RAFIQ ZAKARIA; A$_s$ $_a$ lawyer by profession, the Law Minister is aware that legal aid so far has been a farce and, Sir,, you with your judicial experience, must have also noticed that whatever legal aid has been given so far has been in the form of engaging briefless lawyers who otherwise do not get any brief. I would like to know from the Law Minister, while considering the question of nationalisation of this profession which I do not know, can be done or cannot be done, whether he is also thinking that some kind of compulsion can be

imposed on the leading members of the Bar so that they must be forced to give a part of their time for legal aid.

SHRI SHIV SHANKAR: Sir,... (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: You cannot come in between the two.

SHRI KALYAN ROY: We are sandwiched in between.

SHRI SHIV SHANKAR: As the law exists today ____

DR. RAFIQ ZAKARIA; You can amend the law. ,

SHRI SHIV SHANKAR: i am going to say something. It would be difficult to compel any member of the Bar to take up such cases. But l can assure the House that we would like to persuade the leading members of the Bar to take up these type of cases in the larger interests of the society.

DR. RAFIQ ZAKAIRA: My question Was not about persuation and the hon. Minister knows that the persuasion is going to be an utter failure. I want to know whether he is thinking of taking any legal steps to see....

SHRI SHIV SHANKAR: Mr. Chairman, Sir,, the question was hypothetical, based on the precondition or the pre-conception of nationalisation of the profession. If it is nationalised then perhaps it would be a different course. As I said, we have not as yet considered nationalisation. Therefore, this question does not arise.

MR. CHAIRMAN: I think the question has been adequately answered. *(Interruptions)* I could tell you a lot about legal aid but I am not supposed to do it.

श्री रामानन्द यादव : सभापति जी, जनता सरकार और लोक दल की सरकार के समय में भगवती कमीशन की रिपोर्ट को टर खाने में रख दिया गया था। जहां तक गरीबों के कानूनी मामलों में आर्थिक सहायता देने की बात थी, जनता सरकार और लोक दल दोनों सरकारों ने सम्मिलित रुप से इसे इग्नोर किया। बल्कि जो लीगल एड के रूप में रुपया जिलों में वकीलों को दिया था वह उन्हीं वकीलों को दिया गया जो उनकी पार्टी के थे तथा उसमें भी कमीशन के आधार पर उन गरीबों के केसेज को नेगलेक्ट किया गया। मैं सरकार से दो आश्वासन चाहता हूं पहला आश्वासन यह चाहता हूं . . .

श्री सभापति : आप सवाल कीजिए प्रश्न पूछिए।

SHRI RAMANAND YADAV: Sir, introductory speech is very necessary. That iq why I have to say so much.

मैं सरकार से तीन बातों का आश्वासन चाहता हूं। क्या सरकार लीगल एड की जो मात्रा है—पिछले साल एक लाख रुपया दिया गया था—उसको बढ़ाकर एक करोड़ रुपया कम से कम इस वर्ष या इससे अधिक, भारत भर के हरिजनों की जनसंख्या जो उत्पीडित की जाती है, उसको कानूनी ढंग से सहायता करने के लिए उसमें वृद्धि करेगी ?

दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि डिस्ट्रिक्ट से लेकर प्राविन्स और सब डिवीजन तक जो लायर्स इन्वोज किये जाते है, वे मेधावी अच्छे योग्य नियुक्त किये जायें।

तीसरी बात मैं यह चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि अब तक पिछली जनता सरकार के ढ़ाई वर्ष के शासन काल में लीगल एड पर जो रुपया व्यय हुआ है वह किस तरह

के लायर्स पर व्यय हुआ है। क्या ब्रीफलेस लायर्स पर, पार्टी के इन्वोल्ड लायर्स पर या आइडोलाजिकल लायर्स पर व्यय हुए है क्या सरकार उसकी जांच करायेगी ?

श्री शिव शंकर : जहां तक पहला सवाल है कि हम एक करोड़ रुपये तक लीगल एड के लिये इक्ट्ठा करें, इस ताल्लुक से मैंने पहले ही अर्ज कर दिया हैं कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जहां तक हों सके ज्यादा से ज्यादा लीगल एड के लिये हम रुपया मुहैय्या करें। मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि हाऊस के सेन्टीमैन्टस को देखते हुए और देश के सेंटिमेंटस को देखते हुए हम इस बात की कोशिश करेंगे कि अगले बजट में जितना रुपया जमा हो सकता है उसको लीगल एड के लिये मुहैय्या करेंगे।

दूसरा, जो मेरे मित्र ने कहां कि साहब नीचे की अदालतों के अन्दर क्या ब्रीफलेस लायर्स को ही लीगल एड के मुकद्दमे दिये गये थे या मैं आश्वासन दू कि अच्छे लायर्ज को ही लीगल एड के केसेज दिये जायेंगे, इस ताल्लुक से स्टेट की सरकारों का सहयोग भी जरूरी है

श्री रामानन्द यादव : आप लिखें उनको।

श्री शिव शंकर : मैं यह आश्वासन जरूर देना चाहता हू कि मैं उन स्टेट सरकारों को लिखूंगा जहां तक मेरे मित्र ने कहा कि यह जो ढ़ाई, तीन साल के अन्दर यह जो रकम खर्च की गई है लीगल एड के ताल्लुक से, कोई एन्कवायरी होगी। हम इस बात में विश्वास नहीं करते। हम अपना काम करना जानते है और हम अपना काम करेंगे। पिछला क्या हुआ, सिर्फ खोद कर हड्डियां निकालने से कोई मतलब की बात नहीं है।

SHRI DINESH GOSWAMI; I have been trying to catch your eye from the very beginning. This is very unfair. You have to give chance to all the sidec.

MR. CHAIRMAN: Next one.

SHRI DINESH GOSWAMI: It is very unfair. That is not the way how Question Hour is_____

एक माननीय सदस्य : अपने देश की जो हालत है, जजेंज को भी प्रोटेक्शन देने की बहुत सख्त जरूरत है और इसके वास्ते हमारी गवर्नमेंट आश्वासन दे कि फयूचर में हमारे सुप्रीम कोट तथा हाई कोर्ट के जजेंज को प्रोडेक्शन मिलेगा।.... *Interruptions).*

SHRI A. G. KULKARNI; Courts need not worry.

SHRI DINESH GOSWAMI; The hon. Law Minister is himself deeply interested in the legal aid movement and he was associated with persuading the Government into making this recommendation to the Bhagwati Committee. When the last Government came in, then an Inter-departmental Committee was set up in order to evade the report. The Inter-departmental Committee was set up because the last Janata Government was not keen to provide legal aid. May I know from the hon. Minister, who has a deep knowledge about the legal aid movement whether instand of going through the rigmorale of the Inter-departmental Committee, his Ministry is not competent to examine the report itself and suggest measures to the Government in the background in which he has worked so far.

SHRI SHIV SHANKAR: So far as this question is concerned, I may say this much that the Inter-departmental

Committee has done some good work, , though, of course, it has tiot been able to complete the work.

AN HON. MEMBER: It has taken three years.

SHRI SHIV SHANKAR.- i am sorry for it. Still we have got to simetimes give the necessary time. May I say this much? In fact, the Bhagwati Committee had observed like this:

"इसके पूर्व की स्थाई रूप से किसी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, अनेक प्रकार के अध्ययन करने होंगे। समुचित चित्र तैयार करने से पूर्व ज्ञान की अनेक शाखाओं से समन्वय स्थापित करना होगा।"

It is because of certain observations that were made by the Bhagwati Committee that the matter had to be referred to the Inter-departmental Committee and I am quite confident, Sir,, that the matter would be resolved at the earliest. I am after it and my officers have also taken it seriously. Therefore, I am confident that this matter can be resolved at the earliest.

MR. CHAIRMAN: After this, there is very little to ask, really speaking. Otherwise this will go on. We will pass on to the next question. I disallow any further questions. *(Interruptions)* I am sorry. This has been discussed thread-bare. Questions have been asked. There has been enough material. The assurance is that the Government is seized of the matter and is going to proceed.

SHRI MANUBHAI PATEL: I have a question regarding the fundamental basis of the philosophy they are following.

MR. CHAIRMAN: At some other time. We will now go on to the third question. I have allowed enough sup-plementaries on this. Question No. 3.

Production of Sulphuric Acid by M/S. Hindustan Copper Limited, Khetri

*3. SHRIMATI PRATIMA BOSE:

SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON:!

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Hindustan Copper Limited, Khetri (Rajasthan) has started commercial production of Sulphuric Acid as a basic industrial raw-material; if so, what is it_a installed capacity and actual pro-duction;

(b) what are the norms and condi tions laid down by. Hindustan Copper Limited for distribution/market ing of Sulphuric Acid;

(c) whether it is also a fact that Hindustan Copper Limited are supplying the material to the Co-operative Sector for fair distribution and to curb spurt in prices of essential raw materials;

(d) if so, what are the details in this regard; and

(e) if the answer to part (c) above be in the negative, what are the rea sons therefor?

THE MINISTER OF COMMERCE, STEEL AND MINES AND CIVIL SUPPLIES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Sulphuric Acid Plant at the Khetri Copper Complex (Rajasthan) of Hindustan Copper Limited, has been in operation since October, -1975, utilising the sulphur gase3 arising in copper production. Installed

†he question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Leela Damodara Menon.